

# प्रकृति संरक्षण के अच्छे उदाहरणों की ग्रीन लिस्ट

**आ**म तौर पर प्रजातियों और इकोसिस्टम्स के बचाव से सरोकार रखने वाले समूह रेड लिस्ट प्रकाशित करते हैं जिनसे पता चलता है कि कहां खतरा ज्यादा है। मगर अब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) ने एक ग्रीन लिस्ट प्रकाशित की है। इसमें 23 ऐसे आरक्षित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जहां साज-संभाल अच्छी तरह की जा रही है। यह लिस्ट सिडनी में सम्पन्न विश्व उद्यान सम्मेलन में जारी की गई।

एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति संरक्षण के उपाय काफी सफल रहे हैं। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन में यह लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक पृथ्वी की भूमि के 17 प्रतिशत और समुद्रों के 10 प्रतिशत को सुरक्षित किया जाएगा। राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक फिलहाल 15.4 प्रतिशत भूभाग और 3.4 प्रतिशत समुद्र आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं।

मगर सारे आरक्षित क्षेत्र एक जैसी स्थिति में नहीं हैं। मसलन, ऑस्ट्रेलिया में समुद्री आरक्षित क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ भी शामिल है। मगर *एक्वेटिक कंज़र्वेशन* नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इन आरक्षित क्षेत्रों का समुद्री इकोसिस्टम्स के संरक्षण में कोई खास योगदान नहीं रहा है। इसका कारण यह बताते हैं कि इन आरक्षित क्षेत्रों का चुनाव इकोसिस्टम्स की सुरक्षा के लिहाज़ से नहीं बल्कि इस आधार पर किया गया था कि व्यापारिक कामकाज पर ज्यादा असर न हो।

आई.यू.सी.एन. के ग्रीन लिस्ट प्रोजेक्ट के मुखिया

जेम्स हार्डकासल का कहना है कि सिर्फ आरक्षित क्षेत्र बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका समुचित प्रबंधन भी करना होगा। प्रबंधन के अभाव में ऐसे आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना बेकार ही होगी।

*नेचर* में 14 नवंबर को प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि कुल आरक्षित क्षेत्र फिलहाल दुनिया भर की धरती पर रहने वाली रीढ़धारी प्रजातियों में से मात्र 19 प्रतिशत के प्राकृतवासों में फैले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि जैव विविधता संधि के 2020 के लक्ष्य को पा लिया जाए तो यह संख्या तिगुनी हो सकती है। मगर साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव आने से जैव विविधता पर खतरा बढ़ भी सकता है। एक अनुमान के मुताबिक यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2040 तक कम से कम 1000 ज़ोखिमग्रस्त प्रजातियों का आवास सिकुड़कर आधा रह जाएगा।

आई.यू.सी.एन. ने ग्रीन लिस्ट बनाने के विचार को 2012 में अपनाया था। इसके बाद संघ ने सरकारों से कहा कि वे अपने-अपने देश के आरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल करवाने के लिए नामित करें। इसके लिए 20 मापदंड निर्धारित किए गए थे। अंत में आई.यू.सी.एन. ने 27 प्रस्तावों में से 23 को स्वीकार किया। सफल आरक्षित स्थलों में चीन का मनोरम माउंट हुआंगशान और कोलंबिया का गेलेरस वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन लिस्ट बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि वहां पहले से बसे लोगों के साथ कैसा सलूक किया गया है। (*स्रोत फीचर्स*)